विविध नागरिक

एस.एस. संधावालिया और जे.एम. टंडन से पहले, जे.जे.

सोहन सिंह आदि,-याचिकाकर्ता। /

बनाम

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्य,-प्रतिवादी।

1975 की सिविल रिट संख्या 6544

10 जनवरी 1978.

पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम (1952 का XXVII) - धारा 15 - पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) भवन नियम 1952 - नियम 5 - भारत का संविधान 1950 - अनुच्छेद 14 - उल्लंघन में भवन का निर्माण नियमों का–'अनापत्ति प्रमाणपत्र' जारी करना–क्या उल्लंघनों को माफ करने का प्रभाव है–अनुच्छेद 14—क्या माफी के अन्य उदाहरणों के सामने आकर्षित किया जा सकता है।

माना गया कि 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' स्थानांतरण की सुविधा के उद्देश्य से जारी किया जाता है, न कि पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम 1952 या पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) के किसी भी उल्लंघन को नज़रअंदाज करने के उद्देश्य से। ¬tion) बिल्डिंग नियम, 1952. <

(पैरा 6).

माना गया कि किसी भी क़ानून के तहत अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों से पहले समानता का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और यदि ए। एक मामले में गलत आदेश पारित किया गया है, तो यह दूसरे व्यक्ति को यह कहकर गलत आदेश के समक्ष समानता का दावा करने का अधिकार नहीं देता है कि उसके मामले में भी इसी तरह का गलत आदेश पारित किया जाना चाहिए। भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 14 में निहित दावा कानून के समक्ष है और किसी अधिनियम के तहत कार्यकारी प्राधिकारी का आदेश कानून की श्रेणी में नहीं आता है।

(पैरा 7)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि माननीय न्यायालय प्रसन्न हो:

(ए) सर्टिओरारी, मैंडामस या किसी अन्य आदेश या रिट या निर्देश की रिट जारी करने के लिए जिसे यह माननीय न्यायालय उचित मान सकता है। और मामले की परिस्थितियों में उचित, दिनांक 13 सितंबर, 1974, 30 जनवरी, 1975 और 22 मार्च, 1975 के विवादित नोटिसों को रद्द करना।

(बी) उत्तरदाताओं को इस रिट याचिका और अभ्यावेदन में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई दलीलों पर विचार करते हुए आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाए।

सोहन सिंह आदि बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, आदि।

(जे. एम. डैंडन, जे.)

(सी) मामले की परिस्थितियों में याचिकाकर्ताओं को उत्तरदाताओं को अपेक्षित नोटिस देने से छूट देने के लिए (यानी उत्तरदाता अपने कर्मचारियों के साथ संबंधित संपत्ति को ध्वस्त करने के लिए साइट पर पहुंच गए हैं) और याचिकाकर्ताओं को दाखिल करने से भी छूट दी गई है अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियां।

(डी) उत्तरदाताओं को रिट याचिका के अंतिम निर्णय तक संबंधित संपत्ति को ध्वस्त न करने का निर्देश देना।

(ई) याचिकाकर्ताओं को इस याचिका की लागत का पुरस्कार देना।

कुलदीप सिंह, बार-एट-लॉ मोहन सिंह, एडवोकेट; याचिकाकर्ताओं के लिए.

प्रतिवादियों की ओर से आर.के. छिब्बर, सरकारी वकील यू.टी. चंडीगढ़।

निर्णय.

जे. एम. टंडन, जे.-

(1) सोहन सिंह और अन्य द्वारा दायर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत वर्तमान रिट याचिका एस.सी. संख्या 57-58- के निर्माण से संबंधित रिट याचिका में निर्दिष्ट उत्तरदाताओं के आदेशों के खिलाफ निर्देशित है। 59, सेक्टर 17-सी, चंडीगढ़।

(2) मामले के प्रासंगिक तथ्य, संक्षेप में, यह हैं कि ऊपर वर्णित संपत्ति याचिकाकर्ता संख्या 1 से 7 द्वारा रणजीत सिंह ग्रेवाल आदि से कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई थी - 3 जुलाई 1974 के बिक्री समझौते के माध्यम से। विक्रेताओं के पक्ष में बिक्री का निष्पादन होने से पहले, मूल मालिकों, अर्थात् रणजीत सिंह ग्रेवाल और अन्य (विक्रेताओं) ने चंडीगढ़ प्रशासन से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' के लिए आवेदन किया था जो 13 मई, 1974 को जारी किया गया था। , जिसकी प्रति रिट याचिका का अनुलग्नक पी-1 है। विक्रेताओं ने सितंबर, 1974 में स्लैब आदि बिछाने का काम शुरू किया। 13 सितंबर, 1974 को संपदा अधिकारी ने पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1952 (इसके बाद इसे कहा जाएगा) की धारा 15 के तहत एक नोटिस जारी किया। अधिनियम), जिसमें कहा गया है कि साइट पर उबे निर्माण पंजाब राजधानी (विकास और (विनियमन भवन नियम, 1952 (इसके बाद नियमों के रूप में संदर्भित) के नियम 5 का उल्लंघन था)। 30 सितंबर, 1974 को एक और नोटिस जारी किया गया था।

आई-एल.आर. पंजाब और हरियाणा (1978)1

इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 से 7 अन्य मालिकों के साथ थे। सार्वजनिक बरामदे के नीचे बेसमेंट के ऊपर दोनों तरफ स्लैब बिछा दी, जो नियमावली के नियम 5 का भी उल्लंघन था। याचिकाकर्ताओं ने नोटिस का जवाब समझाते हुए दिया

इसमें कहा गया है कि संपदा/अधिकारी द्वारा जारी 13 मई, 1974 के 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' ने भवन नियमों के उल्लंघन, यदि कोई हो, को वैध ठहराया और आगे अधिनियम की धारा 15 के दूसरे प्रावधान के तहत संरचना के लिए प्रार्थना की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। प्रशासन द्वारा. याचिकाकर्ताओं ने रचना के लिए समीक्षा याचिका दायर की लेकिन सफल नहीं हुए। याचिकाकर्ता संख्या 8 से 21 ने ओम प्रकाश गुप्ता आदि से संपत्ति का आधा हिस्सा खरीदा - 31 जनवरी, 1975 को बिक्री विलेख के माध्यम से। 27 मार्च, 1975 को, याचिकाकर्ताओं को प्रशासन से एक और नोटिस मिला जिसमें उल्लंघन के संबंध में बरामदे के नीचे तहखाने का निर्माण, दरवाजे खोलने और विभाजन की दीवारों आदि का उल्लेख किया गया था। इस नोटिस का उत्तर यह समझाते हुए दिया गया था कि अधिनियम या नियमों के किसी भी प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है और आगे उन्हें संरचना के मामले में इसी तरह के अन्य मामलों के बराबर माना जा सकता है। अधिकारी याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से सहमत नहीं हुए और न ही उल्लंघनों को कम करने के लिए सहमत हुए और इमारत के विध्वंस के आदेश पारित कर दिए। याचिकाकर्ताओं को अपनी मांग को पूरा करने के लिए कोई अन्य उपाय नहीं मिला, उन्होंने वर्तमान रिट याचिका दायर की है जिसमें उन्हें जारी किए गए नोटिस को रद्द करने की प्रार्थना की गई है और उत्तरदाताओं को धारा 15 के दूसरे प्रावधान के तहत यदि कोई उल्लंघन हो तो उसे कम करने का निर्देश दिया गया है। कार्यवाही करना।

(3) उत्तरदाताओं ने अपने लिखित बयान में इस बात से इनकार किया कि ए याचिकाकर्ताओं ने ऊपर निर्दिष्ट भवन के निर्माण में कोई उल्लंघन नहीं किया है। इस बात से भी इनकार किया गया है कि अधिनियम की धारा 15 के दूसरे प्रावधान के तहत रचना के मामले में याचिकाकर्ताओं के साथ कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया है। उनका रुख यह है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए उल्लंघनों की भरपाई कानून के तहत प्राधिकारियों द्वारा नहीं की जा सकती।

(4) उत्तरदाताओं के अनुसार, भवन निर्माण के मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित उल्लंघन किए गए हैं: -

(i) सार्वजनिक बरामदे के नीचे अतिक्रमण करके बेसमेंट का निर्माण;

(ii) अनेक दुकानों का निर्माण;

सोहन सिंह आदि बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, आदि।

(जे. एम. डैंडन, जे.)

(iii) छोटे विभाजनों का निर्माण; और

(iv) अत्यधिक संख्या में दरवाजों का निर्माण।

(5) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री कुलदीप सिंह ने जहां तक (iii) से (iv) उल्लंघन का संबंध है, कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने बहस के दौरान कहा कि इमारत में किए गए कुछ विभाजन पहले ही ध्वस्त कर दिए गए हैं। प्रशासन। किसी भी मामले में, जहां तक उल्लंघन (ii) से (iv) को हटाने का सवाल है, याचिकाकर्ताओं को कोई आपत्ति नहीं है। ,

(6) रिट याचिका में मुख्य रूप से उल्लंघन (i) के संबंध में तर्क दिया गया है, "अर्थात, सार्वजनिक बरामदे के नीचे अतिक्रमण करते हुए बेसमेंट का निर्माण किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि बेसमेंट का निर्माण तब किया गया था जब याचिकाकर्ता संख्या 1 से 8 साथ थे, कुछ अन्य लोगों ने मूल मालिकों से साइट खरीदी। इस उद्देश्य के लिए, 13 मई 1974 के 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' का संदर्भ दिया गया है, जिसमें यह दर्ज है कि "मालिक ने उक्त साइट पर छत तक इमारत खड़ी कर दी है।" बेसमेंट का स्तर। यह तर्क दिया गया है कि यह मानते हुए कि बेसमेंट के निर्माण में सार्वजनिक बरामदे के नीचे अतिक्रमण शामिल है, 13 मई 1974 को 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी होने पर उल्लंघन को माफ कर दिया गया था, और इस तरह अब याचिकाकर्ताओं को नहीं बुलाया जा सकता है। इसे ध्वस्त करने के लिए। हम विद्वान वकील के इस तर्क से सहमत होने में असमर्थ हैं। ए। 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' स्थानांतरण की सुविधा के उद्देश्य से जारी किया जाता है, न कि ^सीटी या नियमों के किसी भी उल्लंघन को माफ करने के उद्देश्य से। यह तर्क दिया गया है कि हो सकता है कि 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' विशेष रूप से उक्त उल्लंघनों को माफ नहीं करता है, लेकिन यह निहितार्थ से ऐसा करता है। इस तर्क में फिर से कोई बल नहीं है। जैसा कि पहले देखा गया है, 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' का उद्देश्य अधिनियम या नियमों के उल्लंघन को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार इसका प्रभाव निहितार्थ से भी नहीं हो सकता है।

(7) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान उत्तरदाताओं के लिखित बयान के पैरा 16(एन) की ओर आकर्षित किया है जिसमें उन मामलों का विवरण है जिनमें कंपोजिशन का आदेश दिया गया था। अधिनियम की धारा 15 के दूसरे प्रावधान के तहत अधिकार दिए गए हैं। विद्वान वकील का तर्क यह है कि वे पिंजरे, जिनमें संरचना की अनुमति दी गई है, वर्तमान मामले के समान हैं और अधिकारियों ने, तत्काल मामले में संरचना की अनुमति न देकर याचिकाकर्ताओं के साथ भेदभाव किया है, विद्वान वकील ने कहा

उत्तरदाताओं ने हमें उन मामलों के तथ्यों से अवगत कराया है और यह स्पष्ट है कि वे मामले वर्तमान मामले से काफी अलग हैं। उदाहरण के लिए, अधिनियम की धारा 15 के पहले प्रावधान के तहत, अधिनियम या नियमों के किसी भी उल्लंघन के लिए इमारत को उसके शुरू होने या पूरा होने के छह महीने की अवधि के भीतर ध्वस्त किया जा सकता है। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने बताया कि लिखित बयान में वर्णित सभी मामलों में छह महीने की वैधानिक अवधि समाप्त हो गई थी। विद्वान वकील ने माना है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा इमारत में किए गए उल्लंघनों को कम करना अधिकारियों की क्षमता में नहीं है। उन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, अमृतसर बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का भी हवाला दिया है, (1) जिसमें यह माना गया था कि किसी भी क़ानून के तहत अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों से पहले समानता का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और यदि कोई गलत आदेश है एक मामले में पारित किया गया है, तो यह दूसरे व्यक्ति को यह कहकर गलत आदेश के समक्ष समानता का दावा करने का अधिकार नहीं देता है कि उसके मामले में भी इसी तरह का गलत आदेश पारित किया जाना चाहिए। आगे यह माना गया कि संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता कानून के समक्ष है और किसी अधिनियम के तहत कार्यकारी प्राधिकारी का आदेश कानून की श्रेणी में नहीं आता है।

(8) इस बिंदु पर पार्टियों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामला उत्तरदाताओं के लिखित बयान में वर्णित के समान नहीं है। यह भी संदिग्ध है कि क्या वर्तमान मामले में शामिल उल्लंघनों को अधिकारियों द्वारा अधिनियम की धारा 15 के दूसरे प्रावधान के तहत समझौता किया जा सकता है।

(9) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि अधिनियम की धारा 15 का दूसरा प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 के दायरे से बाहर है क्योंकि यह इसके आवेदन के लिए कोई दिशानिर्देश प्रदान नहीं करता है। प्रतिवादियों के विद्वान वकील का तर्क यह है कि इस बिंदु को इन कार्यवाहियों में नहीं उठाया जा सकता क्योंकि अधिनियम की धारा 15 के दूसरे प्रावधान की शक्तियों को याचिका में विशेष रूप से चुनौती नहीं दी गई है। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील का तर्क प्रबल होना चाहिए। याचिका में अधिनियम की धारा 15 के दूसरे प्रावधान की शक्तियों को विशेष रूप से चुनौती नहीं दी गई है और इस प्रकार याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को इन कार्यवाही में इस बिंदु पर बहस करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(1) 1975 पी.एल.आर. 354.

राधा राम बद्री नाथ, आदि बनाम अमृतसर चीनी मिल्स कंपनी

लिमिटेड आदि (आर.एस. नरूला, सी.जे.)

(10) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तब तर्क दिया कि बरामदे के नीचे का बेसमेंट ध्वस्त होने की स्थिति में पूरी इमारत गिर जाएगी और याचिकाकर्ताओं को भारी नुकसान होगा। प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान 7 अक्टूबर, 1974 के आवेदन की ओर आकर्षित किया है, (कॉपी अनुलग्नक पी-4), जिसे याचिकाकर्ताओं ने संपदा अधिकारी-सह-उपायुक्त, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ को संबोधित किया था, जिसमें यह कहा गया है विशेष रूप से कहा गया है कि उनके अनुरोध की अनुमति नहीं दिए जाने की स्थिति में, वे बरामदे के नीचे बेसमेंट के कथित अनधिकृत निर्माण को बंद कर देंगे। यदि इस प्रकार तर्क दिया गया है कि बरामदे के नीचे अतिक्रमण हटाने में पूरी इमारत को ध्वस्त नहीं किया जाएगा और, जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने स्वयं कहा है, बेसमेंट के अनधिकृत निर्माण को बिना किसी नुकसान के बंद किया जा सकता है। इमारत के लिए. हम उत्तरदाताओं के विद्वान वकील से सहमत हैं।

(11) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का अंतिम तर्क यह है कि यदि रिट याचिका विफल हो जाती है, तो उन्हें इमारत के बरामदे के नीचे अतिक्रमण हटाने के लिए दो महीने का समय दिया जा सकता है। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील को इस प्रार्थना के स्वीकृत होने पर कोई आपत्ति नहीं है।

(12) ऊपर जो कहा गया है, उसके मद्देनजर, इस रिट याचिका में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जिसे खारिज कर दिया जाए, लेकिन लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं को बरामदे के नीचे बेसमेंट का अतिक्रमण हटाने के लिए दो महीने का समय दिया गया है। इमारत। .

एस.एस.संधवालिया, जे.-मैं सहमत हूं।

के.टी.एस.

पूरी बेंच

, आर.एस. नरूला सी.जे., हरबंस लाल और सुरिंदर से पहले।

सिंह, जे जे.

राधा राम बद्री नाथ और अन्य,-याचिकाकर्ता।

बनाम,

अमृतसर शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड आदि, - प्रतिवादी।

कंपनी याचिका, 1973 की संख्या 150

8 अप्रैल 1977.

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम (1951 का 65) अधिनियम (1953 का 26 और 1971 का 72) द्वारा संशोधित - धारा 18-एए(1) और

स्थानीय : भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है तांकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उददेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उददेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अर्शवीर कौर संधू
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हरियाणा